



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 30, 2017—जनवरी 5, 2018 (पौष 9, 1939)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 30, 2017—JANUARY 5, 2018 (PAUSA 9, 1939)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

पृष्ठ सं.	विषय-सूची	पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	1083	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... *
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2005	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... *
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	11	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... *
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	2331	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 23781
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... *
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... *
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 2765
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 2245
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... *

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1083	by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	2005	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	11	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	2331	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	23781
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2765
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	2245
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 दिसम्बर 2017

संकल्प

सं. 6-4/2010-एमसी (भाग)—भारत के राजपत्र भाग I खंड 1 में दिनांक 03.08.2017 की सं. 6-4/2010-एमसी(पार्ट) द्वारा प्रकाशित इस मंत्रालय के दिनांक 03.08.2017 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में, यह सूचित किया जाता है कि श्री कुनाल के. शाह, अहमदाबाद, गुजरात ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा मॉनीटरिंग समिति (एनएमसीएमई) से त्यागपत्र दे दिया है।

आदेश

यह आदेश किया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश किया जाता है कि यह संकल्प सामान्य सूचनार्थ भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मधु रंजन कुमार
संयुक्त सचिव

संकल्प

विषय : राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा मॉनीटरिंग समिति (एनएमसीएमई) के पुनर्गठन—के संबंध में।

सं. 6-4/2010-एमसी (पार्ट)—राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा मॉनीटरिंग समिति (एनएमसीएमई) के पुनर्गठन के लिए दिनांक 03.08.2017 की सं. 6-4/2010-एमसी(पार्ट) द्वारा भारत के राजपत्र, भाग-I खंड-1 में प्रकाशित इस मंत्रालय के दिनांक 03.08.2017 के समसंख्यक संकल्प के अनुक्रम में समिति ने राज्य सभा और लोक सभा के निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया गया है :—

क्र.सं.	सदस्य का नाम	स्थायी पता	दिल्ली का पता
(i)	श्री मजीद मेमन, संसद सदस्य, राज्य सभा	71, आशियाना, 1 लेन, अल्मीडा पार्क, बांद्रा (पश्चिम), मुंबई-400050	सी-1/9, लोधी गार्डन, राजेश पायलट मार्ग, नई दिल्ली
(ii)	श्री मेघराज जैन, संसद सदस्य, राज्य सभा	नर्सिंग बाजार, इंदौर, मध्य प्रदेश	401, स्वजस डीलक्स, डॉ. बी.डी.मार्ग, नई दिल्ली-110001
(iii)	श्री मुजफ्फर हुसैन बेग, संसद सदस्य, लोक सभा	वाहदीना, बारामुल्ला, जम्मू और कश्मीर	50, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
(iv)	प्रो. रिचर्ड हे, संसद सदस्य, लोक सभा	हेस मनोर, होलोवे रोड, थालासेरी, केरल-670101	डी-2, ए ब्लॉक, एमएस फ्लैट्स, बीकेएस मार्ग, नई दिल्ली-110001

आदेश

यह आदेश किया जाता है कि संकल्प की प्रति समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश किया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

मधु रंजन कुमार
संयुक्त सचिव

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 2017

सं. पी-12014/1/2016-एसपीआर—सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेत तक जल की वास्तविक पहुंच बढ़ाने और कृष्य क्षेत्र में विस्तार करने, और सिंचाई क्षेत्र में निवेश के अभिसरण प्राप्त करने के व्यापक उद्देश्य से, विभिन्न मंत्रालयों के तहत सिंचाई के क्षेत्र में चल रही योजनाओं को मिलाकर वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) शुरू की थी।

पीएमकेएसवाई के घटकों का सरकार के संबंधित मंत्रालयों द्वारा निष्पादित किया जाना जारी रहेगा, जैसाकि पीएमकेएसवाई योजना के शुभारंभ से पहले प्रचालन में था। यानि त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) राष्ट्रीय परियोजनाओं और हर खेत को पानी सहित (उप-घटकों के साथ - सतही लघु सिंचाई, जल निकायों की मरम्मत, नवीकरण और बहाली, कमान क्षेत्र विकास और भूमि जल विकास) जल संसाधन मंत्रालय, आरडी एंड जी आर द्वारा; 'प्रतिबंद अधिक फसल' कृषि, सहकारिता एवं किसान मंत्रालय द्वारा और 'वाटर शेड विकास' ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा।

पीएमकेएसवाई के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए तीनों केन्द्रीय मंत्रालयों को शामिल करके ठोस प्रयास, समग्र समन्वय और परिणाम केन्द्रित निगरानी के साथ; केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 27 जुलाई, 2016 की बैठक में जल संसाधन मंत्रालय, आरडी एंड जी आर मंत्रालय में पीएमकेएसवाई मिशन की स्थापना का प्रस्ताव अनुमोदित किया था।

अब, केन्द्रीय मंत्रिमंडल के उपर्युक्त अनुमोदन के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा पीएमकेएसवाई मिशन का गठन निम्न प्रकार से करता है:

अ. पीएमकेएसवाई की मिशन की संरचना:

1. मिशन की अध्यक्षता जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में अपर सचिव/विशेष सचिव स्तर पर मिशन निदेशक द्वारा की जाएगी। सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता एनडब्ल्यूडीए के वर्तमान स्टाफ से पूरी की जाएगी।
2. मिशन निदेशक की अध्यक्षता में मिशन निदेशालय की कार्यकारी समिति में जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, भू संसाधन विभाग और कृषि, सहभागिता और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी और सीडब्ल्यूसी के संबंधित मुख्य इंजीनियर शामिल होंगे। मुख्य अभियंता (सीई) परियोजना निगरानी, सीडब्ल्यूसी समिति के सदस्य सचिव होंगे। कार्यकारी समिति परिचालनात्मक समावेशन, समन्वय और निगरानी के लिए उत्तरदायी होगी।
3. पीएमकेएसवाई के लिए उत्तरदायी जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भू संसाधन विभाग और कृषि सहभागिता और किसान कल्याण मंत्रालय से संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को अपर मिशन निदेशकों (एएमडी) के रूप में भी पदनामित किया जाएगा। तथापि, मिशन महानिदेशालय का भाग होते हुए और संपूर्ण समन्वय और निगरानी में मिशन निदेशक की सहायता करते हुए एएमडी अपने संबंधित विभागों के सचिवों को रिपोर्ट करेंगे जो पीएमकेएसवाई के अंतर्गत अपने घटकों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी रहेंगे।
4. आईईसी कार्यकलापों, निगरानी और एमआईएस से संबंधित मुद्दों के लिए 99 प्राथमिकता वाली एमएमआई परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता हेतु प्रावधानों के 3% के भीतर स्कीम के कार्यान्वयन के दौरान उत्पन्न हुई कोई अन्य होने वाली किसी प्रकार की अन्य आकस्मिकता हेतु मिशन पर्याप्त संख्या में परामर्शदाताओं को नियुक्त कर सकता है।

(ब) पीएमकेएसवाई मिशन के उद्देश्य:

1. दिसंबर, 2019 तक सीएडी एवं डब्ल्यूएम सहित एआईबीपी के तहत 99 प्राथमिकता दी गई परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करना।

2. किसानों को जल उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक राज्य में 10 प्रतिशत परियोजनाओं में निर्माण कार्य के पूर्ण होने के पश्चात कार्यों तथा इनकी प्रभावकारिता का सामाजिक ऑडिट। समवर्ती मूल्यांकन और तीसरे पक्ष द्वारा 100 प्रतिशत निगरानी की जाएगी।
3. पीएमकेएसवाई के सभी घटकों अर्थात् एआईबीपी एवं एचकेकेपी, एमजीएनआरईजीएस, वाटरशेड विकास, प्रति बूंद अधिक फसल आदि की संपूर्ण समन्वय और परिणाम केंद्रित निगरानी:
 - पूरी सिंचाई क्षमता प्राप्त करना और लक्ष्य के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करना सुनिश्चित करना।
 - जल उपयोग दक्षता में सुधार करना (भूमि और सतही जल दोनों)।
 - सहभागी सिंचाई प्रबंधन और जल प्रयोक्ता संघों और गैर सरकारी संगठनों को बढ़ावा देना।
 - विभिन्न स्कीमों के तहत आपस में मिलाने हेतु बढ़ावा देना।
 - श्रेष्ठ पद्धतियों को साझा करने हेतु मंच प्रदान करना।
 - उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई अन्य अपेक्षित कार्य।
4. मिशन के सभी घटकों के परिणामों की रियल टाईम निगरानी के लिए मिशन में एक एकीकृत निगरानी ढांचे और डैशबोर्ड का विकास।

(स) संयुक्त सचिव व वित्तीय परामर्शदाता के परामर्शानुसार मिशन/मिशन निदेशक को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन

मिशन निदेशक के पास एआईबीपी और सीएडी एवं डब्ल्यूएम के तहत जारी 99 प्राथमिकता वाली परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय हिस्सा जारी और राज्य हिस्से की संस्तुति करने हेतु पूरी शक्तियां होंगी। इसके अतिरिक्त, मिशन निदेशक के पास योजना के तहत इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में समवर्ती मूल्यांकन के संबंध में किए गए खर्च, सामाजिक अंकेक्षण, (प्रत्येक राज्य में परियोजनाओं का 10%), तीसरे पक्ष की निगरानी तथा मूल्यांकन, आईईसी गतिविधियां, अन्य आईटी और पेशेवर सेवाओं, अन्य प्रशासनिक व्यय आदि के लिए मंजूरी / व्यय अनुमोदन करने हेतु पूर्ण शक्तियां होंगी।

अखिल कुमार
संयुक्त सचिव (प्रशासन और भू-जल)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 26th December 2017

RESOLUTION

No. 6-4/2010-MC (Pt.)—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 3.8.2017 published in Gazette of India, Part-I Section.1 vide No. 6-4/2010-MC(Pt.) dated 3.8.2017, it is informed that Shri Kunal K Shah, Ahmedabad, Gujarat has resigned from National Monitoring Committee for Minorities Education(NMCME).

ORDER

Ordered that a copy of the resolution be communicated to the Chairman and other members of the Committee.

Ordered also that the resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADHU RANJAN KUMAR
Joint Secretary

RESOLUTION

Sub: Reconstitution of the National Monitoring Committee for Minorities Education (NMCME)—reg.

No. 6-4/2010-MC (Pt.)—In continuation of this Ministry's Resolution of even number dated 3.8.2017 published in Gazette of India, Part-I Section.1 vide No. 6-4/2010-MC(Pt.) dated 3.8.2017 reconstituting National Monitoring Committee for Minorities Education (NMCME) following members of Rajya Sabha and Lok Sabha have been nominated on the Committee:—

S.No.	Name of the Member	Permanent Address	Delhi Address
(i)	Shri Majeed Memon, MP, Rajya Sabha	71, Aashiyana, 1 st Lane, Almeida Park, Bandra (West), Mumbai-400050	C-1/9, Lodhi Garden, Rajesh Pilot Marg, New Delhi.
(ii)	Shri Meghraj Jain, MP, Rajya Sabha	Narsing Bazar, Indore (M.P.)	401, SWAJAS Deluxe, Dr. B.D. Marg, New Delhi-110001
(iii)	Shri Muzaffar Hussain Baig, MP, Lok Sabha	Wahdina, Baramulla, Jammu and Kashmir	50, Ashoka Road, New Delhi – 110001
(iv)	Prof. Richard Hay, MP, Lok Sabha	Hays Manor, Holloway Road, Thalassery, Kerala – 670 101	D-2, A Block, MS Flats, BKS Marg, New Delhi –110001

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman and other members of the Committee.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MADHU RANJAN KUMAR
Joint Secretary

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT & GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 11th December 2017

No. P.12014/1/2016-SPR—Whereas Government of India in the year 2015-16, launched Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) by amalgamating ongoing schemes in irrigation sector under different Ministries with broad objective of enhancing physical access of water on the farm and expand cultivable area under assured irrigation and achieve convergence of investments in irrigation.

Whereas the components of the PMKSY shall continue to be executed by respective Ministries of Govt. of India under which the component scheme was in operation prior to launch of PMKSY i.e. Accelerated Irrigation Benefit Programme (AIBP) including National Projects and Har Khet Ko Pani (with sub-components-Surface Minor Irrigation, Repair Renovation and Restoration of Water Bodies, Command Area Development and Ground Water Development) by MoWR, RD&GR; 'Per drop more crop' by Ministry of Agriculture, Co-operation & Farmers' Welfare and "Watershed Development" by Ministry of Rural Development.

Whereas to achieve the objectives of PMKSY involving three Union Ministries with concerted effort, overall co-ordination and outcome focused monitoring; Union Cabinet in its meeting dated 27th July, 2016 approved proposal of MoWR, RD&GR for establishment of PMKSY Mission in the Ministry.

Now, in pursuance of the aforesaid approval of the Union Cabinet, Central Government hereby constitutes the PMKSY Mission as follows:

A. Structure of the PMKSY Mission:

1. Mission will be headed by a Mission Director at the level of Additional Secretary/ Special Secretary in the MoWR, RD & GR. The requirement of supporting staff for the Mission would be met from existing staff of NWDA.
2. The Executive Committee of the Mission Directorate headed by Mission Director will consist of Joint Secretary level officers from MoWR, RD & GR, Deptt. of Rural Development, Deptt. of Land Resources and Ministry of Agriculture, Cooperation & Farmers' Welfare and concerned Chief Engineers (CEs) of CWC. CE, Project Monitoring, CWC shall be Member-Secretary of the Committee. The Executive Committee will be responsible for operational convergence, coordination and monitoring.
3. Joint Secretary level officers of MoWR, RD & GR, Deptt. of Rural Development, Deptt. of Land Resources and Ministry of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare responsible for PMKSY shall also be designated as Additional Mission Directors (AMD). However, while being part of Mission Directorate and assisting Mission Director in overall coordination and monitoring, the AMDs shall report to Secretaries of their respective Departments, who shall remain responsible for execution of their components under PMKSY.
4. Mission may engage appropriate number of consultants for IEC activities, monitoring and MIS related issues and any other contingency that may arise during implementation of the scheme from within provision of 3% of provisions for Central Assistance to 99 prioritized Major & Medium Irrigation projects.

B. Objectives of the PMKSY Mission:

1. Ensure completion of 99 prioritized AIBP projects including their Command Area Development & Watershed Management works by Dec. 2019.
2. Social audit of works and its efficacy to make water available to farmers after completion of works in 10% of projects in each state. Concurrent evaluation and 100% third party monitoring.
3. Overall coordination and outcome focused monitoring of all components of PMKSY i.e. AIBP & HKKP, Per Drop More Crop and Watershed Development to:
 - Realize full irrigation potential and ensure completion of projects as per target
 - Improve water use efficiency (Both Ground and Surface Water)
 - Promote Participatory Irrigation Management and formation of Water User Associations and NGOs
 - Promote convergence under various schemes
 - Provide platform to share best practices
 - Any other work required to achieve the objectives
4. Development of Integrated monitoring framework and dashboard in the Mission for real time monitoring of the outcomes of all components of the Yojna.

C. Financial Delegation Powers to Mission/ Mission Director in consultation with JS&FA:

Mission Director shall have full powers to sanction release of Central share in respect of 99 on-going prioritized projects under AIBP and their CAD&WM works. Further, Mission Director shall have full powers to sanction/ approve expenditure to be incurred in respect of concurrent evaluation, social audit (10% of the projects in each state), third party monitoring and evaluation, IEC activities, other IT and professional services, other administrative expenses etc. in implementation of these projects under the Yojna.

AKHIL KUMAR
Joint Secretary (A&GW)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ई-प्रकाशित, 2017
UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2017

www.dop.nic.in